



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 30, 2011/भाद्र 8, 1933

No. 178]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 30, 2011/BHADRA 8, 1933

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 30 अगस्त, 2011

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2011

फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2011-12/22/27668.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2011 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में, -

(i) विनियम 24, इसके पार्श्व टिप्पण के साथ, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जायेगा, अर्थात् :-

"आस्ति प्रबंध कंपनी के कारबार क्रियाकलापों पर निर्बंधन

24. आस्ति प्रबंध कंपनी, -

(क) किसी पारस्परिक निधि के न्यासी के रूप में कार्य नहीं करेगी ;

(ख) कोई ऐसे कारबार क्रियाकलाप नहीं करेगी जो पुलित आस्तियों जिनमें अपतटीय निधियाँ, बीमा निधियाँ, पेंशन निधियाँ, भविष्य निधियाँ

सम्मिलित हैं को दी जाने वाली प्रबंध तथा सलाहकार सेवाओं के स्वरूप से भिन्न हों, यदि ऐसे क्रियाकलापों में से कोई क्रियाकलाप पारस्परिक निधियों के क्रियाकलापों के विरोध में न हों :

परंतु यह कि आस्ति प्रबंध कंपनी स्वयं या अपने समनुषंगियों के माध्यम से ऐसे क्रियाकलाप कर सकेगी, खंड (ख) के अधीन यथा अनुज्ञात, यदि -

- (i) यह इस बात के प्रति बोर्ड का समाधान कर देती है कि बैंक और प्रतिभूति लेखे क्रियाकलाप-वार अलग-अलग रखे जाते हैं ;
- (ii) यह पूँजी पर्याप्तता अपेक्षाओं, यदि कोई हों, को पूरा करती है, ऐसे प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए अलग-अलग, और पृथक् अनुमोदन अभिप्राप्त करती है, यदि सुसंगत विनियमों के अधीन आवश्यक हो ;
- (iii) यह सुनिश्चित करती है कि भिन्न-भिन्न क्रियाकलापों में कोई तात्त्विक हित-संघर्ष नहीं है ;
- (iv) हित-संघर्ष का अभाव न्यासियों और यूनिटधारकों को स्कीम सूचना दस्तावेज तथा अतिरिक्त जानकारी के विवरण में प्रकट किया जायेगा ;
- (v) हित-संघर्ष की अपरिहार्य परिस्थितियाँ हों, तो यह स्वयं का समाधान करेगी कि उस संघर्ष के स्रोत, विनिधानकर्ता (निवेशक) हितों के लिए संभाव्य 'तात्त्विक जोखिम या नुकसान' और उसके लिए विस्तृत मानदंडों के प्रकटीकरण किये जाते हैं ;
- (vi) यह इसके द्वारा प्रबंधित प्रत्येक पृथक् निधि के लिए पृथक् निधि प्रबंधक नियुक्त करती है जब तक कि विनिधान उद्देश्य और आस्ति आबंटन वही न हो और निधि प्रबंधक द्वारा प्रबंधित समस्त निधियों में पोर्टफोलियो का दोहराव न हो, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2011 की अधिसूचना की तारीख से छह महीनों की अवधि के भीतर ;
- (vii) यह उन विभिन्न उत्पादों (प्रोडक्ट्स) में विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) से उचित व्यवहार को सुनिश्चित करती है जिनके अंतर्गत एक ही इक्विटी प्रतिभूति में केवल बाजार तंत्र तथा लिखित व्यापार आदेश प्रबंध प्रणाली के माध्यम से साथ-साथ क्रय और विक्रय, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं, सम्मिलित होंगे ; और
- (viii) यह सुनिश्चित करती है कि सुसंगत आस्ति प्रबंध कंपनी के कार्मिक को पारिश्रमिक और उस क्रियाकलाप द्वारा जनित आमदनी के बीच सीधे संबंध को हटाकर सुसंगत हित-संघर्ष को प्रबंधित करने वाले मुख्य कार्मिकों को स्वतंत्रता दी जाती है :

परंतु यह और कि आस्ति प्रबंध कंपनी, स्वयं या इसकी समनुषंगियों के माध्यम से, अगले निदेशों तक व्यापक आधारीय निधि से भिन्न हेतु संविभाग (पोर्टफोलियो) प्रबंध सेवाओं तथा सलाहकार सेवाओं का जिम्मा ले सकेगी, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन किये जाने के अधीन :-

- (i) यह इस बात के प्रति बोर्ड का समाधान कर देती है कि आस्ति प्रबंध कंपनी के मुख्य कार्मिक, प्रणाली, बैंक ऑफिस, बैंक तथा प्रतिभूति लेखे क्रियाकलाप-वार अलग-अलग रखे जाते हैं और विभिन्न क्रियाकलापों की अंदरूनी जानकारी तक पहुँच रखने से प्रतिषिद्ध करने के लिए प्रणाली विद्यमान है ;
- (ii) यह पूँजी पर्याप्तता अपेक्षाओं, यदि कोई हों, को पूरा करती है, ऐसे क्रियाकलापों में से प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए अलग-अलग, और पृथक् अनुमोदन अभिप्राप्त करती है, यदि सुसंगत विनियमों के अधीन आवश्यक हो ।

स्पष्टीकरण :- इस विनियम के प्रयोजन के लिए, शब्द "व्यापक आधारीय निधि" से वह निधि अभिप्रेत होगी जिसमें कम से कम बीस विनिधानकर्ता (निवेशक) हों और किसी भी एकल विनिधानकर्ता का निधि के कॉर्पस में पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो ।

- (ii) विनियम 25 में, उप-विनियम (16) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :-

"(17) आस्ति प्रबंध कंपनी इसकी किसी भी स्कीम में विनिधान (निवेश) नहीं करेगी, जब तक कि विनिधान करने के इसके आशय का पूर्ण प्रकटीकरण प्रस्ताव दस्तावेजों में न कर दिया गया हो, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2011 की अधिसूचना के पश्चात् लायी गयी स्कीमों के मामले में :

परंतु यह कि आस्ति प्रबंध कंपनी उस स्कीम में इसके विनिधान (निवेश) पर कोई फीस प्रभारित करने की हकदार नहीं होगी ।

(18) आस्ति प्रबंध कंपनी भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर अपने कामकाज नहीं करेगी, जिसमें ट्रेडिंग डैस्क, यूनिटधारक सेवा (सर्विसिंग) तथा विनिधान (निवेश) का कामकाज सम्मिलित है :

परंतु यह कि आस्ति प्रबंध कंपनी जिसके कोई भी कामकाज भारत के बाहर हों भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2011 की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उनका परिसमापन करेगी और उन्हें भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर लायेगी :

परंतु यह और कि बोर्ड एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि प्रदान कर सकेगा यदि इसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर भारत के बाहर के कामकाज का परिसमापन न करने का पर्याप्त कारण था ।"

- (iii) विनियम 36 में, उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(4) आस्ति प्रबंध कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक कलेंडर महीने के लिए समेकित लेखा विवरण, उत्तरवर्ती महीने के दसवें दिन को या उससे पहले जारी किया जाता है, महीने के समाप्ति पर सभी संव्यवहारों तथा धारिता (होलिडिंग) के ब्यौरे देते हुए जिसमें वितरक को अदा किये गये संव्यवहार प्रभार सम्मिलित हैं, सभी पारस्परिक निधियों की सभी स्कीमों में, उन सभी विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को जिनके फोलियो में संव्यवहार उस महीने के दौरान हुए हों :

परंतु यह कि आस्ति प्रबंध कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक छमाही (सितम्बर / मार्च) में समेकित लेखा विवरण जारी किया जाता है, उत्तरवर्ती महीने के दसवें दिन को या उससे पहले, छह महीनों की समाप्ति पर धारिता के ब्यौरे देते हुए, सभी पारस्परिक निधियों की सभी स्कीमों में, ऐसे सभी विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को जिनके फोलियो में कोई भी संव्यवहार उस अवधि के दौरान न हुए हों :

परंतु यह और कि आस्ति प्रबंध कंपनी समेकित लेखा विवरण भेजने के प्रयोजनों के लिए निधि घरानों में से सामान्य विनिधानकर्ता (निवेशक) की पहचान उनकी स्थायी खाता संख्या से करेगी ।

स्पष्टीकरण :- इस विनियम के प्रयोजन के लिए, शब्द "संव्यवहार" में क्रय, मोचन, स्विच, लाभांश पे-आउट, लाभांश पुनर्विनिधान (पुनर्निवेश), व्यवस्थित विनिधान (निवेश) योजना, वापस लिये जाने संबंधी व्यवस्थित योजना, व्यवस्थित अंतरण योजना और बोनस संव्यवहार सम्मिलित हैं ।

- (iv) विनियम 43 में, उप-विनियम (1) में -

(क) खंड (च) में, अंत में, चिह्न तथा शब्द "; या" प्रतिस्थापित हो जायेंगे ;

(ख) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(छ) अवसंरचना ऋण लिखत और आस्तियों जैसा विनियम 495 के खंड (1) में विनिर्दिष्ट है"

- (v) विनियम 44 में, उप-विनियम (3) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जायेगा, अर्थात्:-

"(3) इन विनियमों के अधीन अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, पारस्परिक निधि किसी प्रयोजन के लिए कोई ऋण नहीं देगी ।"

- (vi) अध्याय VI के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय और विनियम अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :-

"अध्याय VI-ख अवसंरचना ऋण निधि स्कीमें"

परिभाषाएँ

- 49ठ. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
- (1) "अवसंरचना ऋण निधि स्कीम" से वह पारस्परिक निधि स्कीम अभिप्रेत है जो प्राथमिक रूप से (स्कीम की आस्तियों का न्यूनतम 90%) अवसंरचना कंपनियों या अवसंरचना पूँजी कंपनियों या अवसंरचना परियोजनाओं या विशेष प्रयोजन वाहनों जो अवसंरचना में विनिधान (निवेश) को सुकर बनाने या का संवर्धन करने के प्रयोजनार्थ सृजित हैं की ऋण प्रतिभूतियों या प्रतिभूत ऋण लिखत, और इन विनियमों के अनुसार अन्य अनुज्ञेय आस्तियों या अवसंरचना कंपनियों या परियोजनाओं या विशेष प्रयोजन वाहनों की पूर्ण तथा आमदनी जनित करने वाली परियोजनाओं की बाबत बैंक ऋणों में विनिधान (निवेश) करती है।
 - (2) "अवसंरचना" के अंतर्गत समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट या वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्र सम्मिलित हैं।
 - (3) "स्ट्रेटेजिक निवेशक" से अभिप्रेत है :
 - (i) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक से रजिस्ट्रीकृत अवसंरचना वित्त कंपनी;
 - (ii) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ;
 - (iii) अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय वित्तीय संस्था।

49ड. लागू होना

- (1) इस अध्याय के उपबंध पारस्परिक निधियों द्वारा लायी गयी अवसंरचना ऋण निधि स्कीमों पर लागू होंगे।
- (2) इन विनियमों के अन्य सभी उपबंध और मार्गदर्शक सिद्धांत और तदधीन जारी परिपत्र, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो या इस अध्याय के उपबंधों के विरुद्ध न हो, अवसंरचना ऋण निधि स्कीमों, ऐसी स्कीमों के संबंध में न्यासियों और आस्ति प्रबंध कंपनियों पर लागू होंगे।

49६. अवसंरचना ऋण निधि स्कीम लाये जाने के लिए पात्रता मानदंड

- (1) विद्यमान पारस्परिक निधि अवसंरचना ऋण निधि स्कीमें ला सकेगी यदि इसके पास पर्याप्त संख्या में मुख्य कार्मिक हों जिनके पास अवसंरचना क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव हो ।
- (2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र विनियम 9 के अधीन केवल अवसंरचना ऋण निधि स्कीमें लाने का प्रस्ताव करने वाले आवेदक को प्रदान किया जा सकेगा यदि प्रायोजक या प्रायोजक की मूल कंपनी :-
 - (क) कम से कम पाँच वर्षों की अवधि से अवसंरचना वित्त-संबंधी क्षेत्र में क्रियाकलाप या कारबार कर रही हो ;
 - (ख) विनियम 7 में उपबंधित पात्रता मानदंड को पूरा करती है ।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन के लिए, 'प्रायोजक की मूल कंपनी' से वह कंपनी अभिप्रेत होगी जो प्रायोजक की समादत्त इक्विटी शेयर पूँजी का कम से कम 75% धारण करती हो ।

49७. अवसंरचना ऋण निधि स्कीमों के लिए शर्तें

- (1) अवसंरचना ऋण निधि स्कीम, या तो सीमित अवधि वाली स्कीम (संवृत स्कीम) जो पाँच वर्ष से अधिक की अवधि के पश्चात् परिपक्व हो रही हो या अंतरावधिक स्कीम जिसकी पाँच वर्षों की अवसंरचना (लॉक-इन) हो तथा अंतराल अवधि एक माह से अधिक लंबी न हो के रूप में लायी जायेगी, जैसा स्कीम के सूचना दस्तावेज में विनिर्दिष्ट किया जाये ।
- (2) अवसंरचना ऋण निधि स्कीमों की यूनिटों को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जायेगा, परंतु यह कि ऐसी यूनिटें पूर्णतः समादत्त होने के पश्चात् ही सूचीबद्ध की जायेंगी ।
- (3) पारस्परिक निधियाँ अवसंरचना ऋण निधि स्कीम का सूचक पोर्टफोलियो इसके संभाव्य विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को प्रकट कर सकेंगी, आस्तियों के प्रकार को प्रकट करते हुए जिनमें पारस्परिक निधियाँ विनिधान (निवेश) करेंगी ।

- (4) अवसंरचना ऋण निधि स्कीम में न्यूनतम पाँच विनिधानकर्ता (निवेशक) होंगे और कोई भी एकल विनिधानकर्ता स्कीम की शुद्ध आस्तियों का पचास प्रतिशत से अधिक धारण नहीं करेगा।
- (5) कोई भी अवसंरचना ऋण निधि स्कीम किसी विनिधानकर्ता से कोई विनिधान (निवेश) नहीं स्वीकारेगी जो एक करोड़ रुपये से कम हो।
- (6) यूनिट का न्यूनतम आकार दस लाख रुपये होगा।
- (7) अवसंरचना ऋण निधि स्कीम के रूप में लायी गयी प्रत्येक स्कीम स्ट्रेटेजिक विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) से कम से कम पच्चीस करोड़ रुपये की रकम के अंशदान के लिए पक्की प्रतिबद्धता लेगी, स्कीम की यूनिटों के आबंटन का विपणन अन्य संभाव्य विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को किये जाने से पहले।
- (8) अवसंरचना ऋण निधि स्कीम लाने वाली पारस्परिक निधियाँ विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को अंशतः संदत्त यूनिटें निर्गमित कर सकेंगी, निम्नलिखित शर्तों के अधीन :
 - (क) आस्ति प्रबंध कंपनी असंदत्त हिस्से की मांग करेगी, अभिनियोजन के अवसरों पर निर्भर रहते हुए ;
 - (ख) स्कीम का प्रस्ताव दस्तावेज़ ब्याज और शास्ति को प्रकट करेगा जिसकी कटौती विनिधानकर्ता (निवेशक) द्वारा नियत समय के भीतर मांग-राशि का भुगतान न किये जाने के मामले में की जा सकेगी ; और
 - (ग) ब्याज या शास्ति की रकम स्कीम में रखी जायेगी।

49त. अनुज्ञेय विनिधान (निवेश)

- (1) प्रत्येक अवसंरचना ऋण निधि स्कीम, स्कीम की शुद्ध आस्तियों का कम से कम नब्बे प्रतिशत, अवसंरचना कंपनियों या परियोजनाओं या विशेष प्रयोजन वाहनों जो अवसंरचना में विनिधान (निवेश) को सुकर बनाने या का संवर्धन करने के प्रयोजनार्थ सृजित हैं की ऋण प्रतिभूतियों या प्रतिभूत ऋण लिखतों, या अवसंरचना कंपनियों या विशेष प्रयोजन वाहनों की पूर्ण तथा आमदनी जनित करने वाली परियोजनाओं की बाबत बैंक ऋणों में विनिधान (निवेश) करेगी।

- (2) उप-विनियम (1) के अधीन, प्रत्येक अवसंरचना ऋण निधि स्कीम शेष रकम इक्विटी शेयरों, संपरिवर्तनीयों जिनके अंतर्गत अवसंरचना, अवसंरचना विकास परियोजनाओं में लगी हुई कंपनियों के मेजेनाइन वित्त-संबंधी लिखत सम्मिलित हैं, चाहे भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों या नहीं; या मुद्रा बाजार लिखतों और बैंक निक्षेपों में विनिधान (निवेश) कर सकेगी।
- (3) निवेश निर्बंधन अवसंरचना ऋण निधि स्कीम के जीवन-चक्र पर लागू होंगे और जिन्हें अवसंरचना ऋण निधि स्कीम द्वारा जुटायी गयी कुल रकम के संदर्भ में गिना जायेगा।
- (4) कोई भी पारस्परिक निधि, अपनी सभी अवसंरचना ऋण निधि स्कीमों के अधीन, इसकी शुद्ध आस्तियों के तीस प्रतिशत से अधिक का विनिधान (निवेश) किसी एकल अवसंरचना कंपनी या परियोजना या विशेष प्रयोजन वाहनों जो अवसंरचना में विनिधान (निवेश) को सुकर बनाने या का संवर्धन करने के प्रयोजनार्थ सृजित हैं की ऋण प्रतिभूतियों या आस्तियों या किसी एकल अवसंरचना कंपनी या परियोजना या विशेष प्रयोजन वाहन की पूर्ण तथा आमदनी जनित करने वाली परियोजनाओं की बाबत बैंक ऋणों में नहीं करेगी।
- (5) कोई अवसंरचना ऋण निधि स्कीम, स्कीम की शुद्ध आस्तियों के 30% प्रतिशत से अधिक का विनिधान (निवेश) किसी एकल अवसंरचना कंपनी या परियोजना या विशेष प्रयोजन वाहनों जो अवसंरचना में विनिधान (निवेश) को सुकर बनाने या का संवर्धन करने के प्रयोजनार्थ सृजित हैं की ऋण लिखतों या आस्तियों या किसी एकल अवसंरचना कंपनी या परियोजना या विशेष प्रयोजन वाहन जिनकी रेटिंग विनिधान (निवेश) श्रेणी से नीचे की हो या जिनकी रेटिंग हुई न हो की पूर्ण तथा आमदनी जनित करने वाली परियोजनाओं की बाबत बैंक ऋणों में नहीं करेगी :

परंतु यह कि ऐसी विनिधान (निवेश) सीमा न्यासी बोर्ड तथा आस्ति प्रबंध कंपनी के बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से स्कीम की शुद्ध आस्तियों के 50% तक बढ़ायी जा सकेगी।

- (6) कोई भी अवसंरचना ऋण निधि स्कीम -

- (i) प्रायोजक या इसके सहयुक्त या समूह कंपनी की किसी असूचीगत प्रतिभूति में ;
- (ii) प्रायोजक या इसके सहयुक्त या समूह कंपनी द्वारा अधिमानी आबंटन के रूप में निर्गमित किसी असूचीगत प्रतिभूति में ;
- (iii) प्रायोजक या इसके सहयुक्त या समूह कंपनी की किसी सूचीबद्ध प्रतिभूति अथवा प्रायोजक या इसके सहयुक्त या समूह कंपनियों की अवसंरचना कंपनियों या विशेष प्रयोजन वाहनों की पूर्ण तथा आमदनी जनित करने वाली परियोजनाओं की बाबत बैंक ऋण में, स्कीम की शुद्ध आस्तियों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक, न्यासियों के अनुमोदन और उपर्युक्त सीमाओं के भीतर किये गये विनिधानों (निवेशों) के लिए विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को पूर्ण प्रकटीकरणों के अध्यक्षीन, ; या
- (iv) प्रायोजक या आस्ति प्रबंध कंपनी या इसके सहयुक्तों की अपनी स्वयं की किसी आस्ति या प्रतिभूति में, स्कीम जो विनिधान (निवेश) श्रेणी से नीचे की न हो की शुद्ध आस्तियों के 20% से अधिक, न्यासियों के अनुमोदन और उपर्युक्त सीमाओं के भीतर किये गये विनिधानों (निवेशों) के लिए विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को पूर्ण प्रकटीकरणों के अध्यक्षीन,

विनिधान (निवेश) नहीं करेगी ।

49थ. आस्तियों का मूल्यांकन और शुद्ध आस्ति मूल्य की घोषणा

- (1) अवसंरचना ऋण निधि स्कीम द्वारा धारित आस्तियों का मूल्यांकन आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा न्यासियों द्वारा अनुमोदित सिद्धांतों के आधार पर समुचित मूल्यांकन पद्धतियों के आधार पर "सद्भावपूर्वक" किया जायेगा।
- (2) मूल्यांकन का दस्तावेजीकरण किया जायेगा और इस प्रकार मूल्यांकित प्रत्येक प्रतिभूति के बारे में समर्थक आँकड़े स्कीम की समाप्ति के पश्चात् कम से कम पाँच वर्षों की अवधि के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे ।
- (3) "सद्भावपूर्वक" मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल की गयी पद्धतियों की समीक्षा पारस्परिक निधियों के न्यासियों द्वारा और कानूनी लेखापरीक्षकों द्वारा आवधिक रूप से की जायेगी ।

3323 GI/11-3

- (4) आस्ति प्रबंध कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन नीति को स्कीम सूचना दस्तावेज में प्रकट किया जायेगा।
- (5) प्रत्येक अवसंरचना ऋण निधि स्कीम के शुद्ध आस्ति मूल्य की गणना की जायेगी और कम से कम प्रत्येक तिमाही में इसकी घोषणा की जायेगी।

49द. आस्ति प्रबंध कंपनी के कर्तव्य

- (1) आस्ति प्रबंध कंपनी आंतरिक नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन की यथोचित प्रणाली अधिकथित करेगी।
- (2) आस्ति प्रबंधक कंपनी अवसंरचना ऋण निधि स्कीम की आस्तियों को बनाए रखने में सम्यक् तत्परता का पालन करेगी और सुनिश्चित करेगी कि उनके मूल्य में कोई परिहार्य क्षय नहीं है।
- (3) आस्ति प्रबंध कंपनी अवसंरचना कंपनियों की आस्तियों को खरीदने या बेचने में अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया के ब्यौरे ऐसे निर्णयों के लिए औचित्यों के साथ लिखित रूप में अभिलिखित करेगी और इसे समय-समय पर न्यासियों को प्रेषित करेगी।
- (4) आस्ति प्रबंध कंपनी सुनिश्चित करेगी कि अवसंरचना निधि स्कीमों की निधियों का विनिधान इस अध्याय के उपबंधों और न्यासी विलेख के प्रतिकूल नहीं किया जाता है।
- (5) आस्ति प्रबंध कंपनी, इन विनियमों के अधीन जब भी अपेक्षित हो, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) जिसमें (जिनमें) यूनिटें सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित हों, से सैद्धांतिक पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- (6) आस्ति प्रबंध कंपनी ऐसी प्रणालियों की स्थापना करेगी जिससे यह सुनिश्चित हो कि ऋण आस्तियों के संग्रहण, अनुश्रवण और पर्यवेक्षण के लिए इसका व्यापक अनुभव रखनेवाले सेवा प्रदाता की नियुक्ति करते हुए, यदि अपेक्षित हो, समुचित देखरेख की जा रही है।

49घ. प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकटीकरण और अन्य प्रकटीकरण

- (1) अवसंरचना ऋण निधि स्कीमों के प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकटीकरण जो विनिधानकर्ताओं द्वारा सोच-समझकर विनिधान निर्णय लेने के लिए

पर्याप्त हों तथा ऐसे और प्रकटीकरण अंतर्विष्ट होंगे जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएँ।

- (2) अवसंरचना ऋण निधि स्कीमों के बारे में पोर्टफोलियो प्रकटीकरणों और वित्तीय परिणामों में ऐसे और प्रकटीकरण अंतर्विष्ट होंगे जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएँ।
- (3) अवसंरचना ऋण निधि स्कीमों के बारे में विज्ञापन ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होंगे जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएँ।

49न. कर्मचारियों इत्यादि द्वारा संव्यवहार

- (1) कंपनियों, जिनमें विनिधान किया जाता है, में आस्ति प्रबंध कंपनी या न्यासी कंपनी के न्यासियों या कर्मचारियों या निदेशकों द्वारा किये गये सभी संव्यवहारों को उनके द्वारा संव्यवहार के एक महीने के भीतर अनुपालना अधिकारी को प्रकट किया जायेगा।
- (2) अनुपालना अधिकारी संभव हित-संघर्ष की दृष्टि से उस पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे अपनी सिफारिशों, यदि कोई हो, के साथ न्यासियों को प्रस्तुत करेगा।
- (3) उप-विनियम (1) में समाविष्ट व्यक्ति कंपनियों, जिनमें विनिधान किया जाता है, में संव्यवहार करने से पहले न्यासियों के विचार अभिप्राय प्राप्त करेंगे, उनसे यथोचित अनुरोध करते हुए।

(vii) विनियम 56 में, -

क. उप-विनियम (1) में, पूर्ण विराम का चिह्न "।", चिह्न ":" से प्रतिस्थापित हो जायेगा ;

ख. उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि स्कीमवार वार्षिक रिपोर्ट या उसका संक्षिप्त सार विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रकार से उनके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जा सकेगा।" ;

ग. उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(4) आस्ति प्रबंध कंपनी पूर्ण स्कीमवार वार्षिक रिपोर्टों का लिंक प्रमुखता से अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगी।"

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :-

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996, मूल विनियम, का.आ. सं. 856(अ), 9 दिसम्बर 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 तत्पश्चात् -

- (क) 15 अप्रैल 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 327 (अ), द्वारा
- (ख) 12 जनवरी 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 32 (अ), द्वारा
- (ग) 8 दिसम्बर 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 1223 (अ), द्वारा
- (घ) 14 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 235 (अ), द्वारा
- (ङ) 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 278 (अ), द्वारा
- (च) 22 मई 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 484 (अ), द्वारा
- (छ) 23 जनवरी 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 69 (अ), द्वारा
- (ज) 29 मई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476 (अ), द्वारा
- (झ) 23 जुलाई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 698 (अ), द्वारा
- (ञ) 20 फरवरी 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 219 (अ), द्वारा
- (ट) 11 जून 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 625 (अ), द्वारा
- (ठ) 30 जुलाई 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 809 (अ), द्वारा
- (ड) 9 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 956 (अ), द्वारा
- (ढ) 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं. 1045 (अ), द्वारा

- (ग) 29 मई 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 632 (अ), द्वारा
- (त) 12 जनवरी 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2004, फा.सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/4/2004, द्वारा
- (थ) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398 (अ), द्वारा
- (द) 12 जनवरी 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 38(अ), द्वारा
- (घ) 22 मई 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 783(अ), द्वारा
- (न) 3 अगस्त 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1254(अ), द्वारा
- (प) 27 दिसम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2006, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/82534/2006, द्वारा
- (फ) 27 दिसम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2006, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/83065/2006, द्वारा
- (ब) 28 मई 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2007/2518, द्वारा
- (भ) 31 अक्टूबर 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2007/4646, द्वारा
- (म) 31 मार्च 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फ्रीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2008/21669, द्वारा
- (य) 16 अप्रैल 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं. एलएजी-एनआरओ/जीएन/2008/03/123042, द्वारा
- (यक) 22 मई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008, सं. एल.ए.डी.-एन.एन.ओ./जी.एन./2008/09/126202, द्वारा
- (यख) 29 सितम्बर 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2008, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/24/139426, द्वारा
- (यग) 8 अप्रैल 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/01/159601, द्वारा
- (यघ) 5 जून 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/07/165404, द्वारा
- (यङ) 29 जुलाई 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/13/13945, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

3323 GI/11-4

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th August, 2011

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (MUTUAL FUNDS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2011

F. No. LAD-NRO/GN/2011-12/22/27668.—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, namely :—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2011.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, -

- (i) regulation 24, along with its marginal note, shall be substituted with the following, namely: -

“Restrictions on business activities of the asset management company

24. The asset management company shall, -

- (a) not act as a trustee of any mutual fund;
- (b) not undertake any business activities other than in the nature of management and advisory services provided to pooled assets including offshore funds, insurance funds, pension funds, provident funds, if any of such activities are not in conflict with the activities of the mutual fund:

Provided that the asset management company may itself or through its subsidiaries undertake such activities, as permitted under clause (b), if,

- (i) it satisfies the Board that bank and securities accounts are segregated activity wise;
- (ii) it meets with the capital adequacy requirements, if any, separately for each such activity and obtain separate approval, if necessary under the relevant regulations;
- (iii) it ensures that there is no material conflict of interest across different activities;
- (iv) the absence of conflict of interest shall be disclosed to the trustees and unit holders in scheme information document and statement of additional information;
- (v) there are unavoidable conflict of interest situations, it shall satisfy itself that disclosures are made of source of conflict, potential ‘material risk or damage’ to investor interests and detailed parameters for the same;

- (vi) it appoints separate fund manger for each separate fund managed by it unless the investment objectives and asset allocation are same and the portfolio is replicated across all the funds managed by the fund manger, within a period of six months from the date of notification of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2011;
- (vii) it ensures fair treatment of investors across different products that shall include, but not limited to, simultaneous buy and sell in the same equity security only through market mechanism and a written trade order management system; and
- (viii) it ensures independence to key personnel handling the relevant conflict of interest is provided through removal of direct link between remuneration to relevant asset management company personnel and revenues generated by that activity;

Provided further that the asset management company may, itself or through its subsidiaries, undertake portfolio management services and advisory services for other than broad based fund till further directions, as may be specified by the Board, subject to compliance with the following additional conditions:-

- (i) it satisfies the Board that key personnel of the asset management company, the system, back office, bank and securities accounts are segregated activity wise and there exist system to prohibit access to inside information of various activities;
- (ii) it meets with the capital adequacy requirements, if any, separately for each of such activities and obtain separate approval, if necessary under the relevant regulations.

Explanation: - For the purpose of this regulation, the term 'broad based fund' shall mean the fund which has at least twenty investors and no single investor account for more than twenty five percent of corpus of the fund.

- (ii) in regulation 25, after sub-regulation (16), the following sub-regulations shall be inserted, namely: -

“(17) The asset management company shall not invest in any of its scheme, unless full disclosure of its intention to invest has been made in the offer documents, in case of schemes launched after the notification of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2011:

Provided that an asset management company shall not be entitled to charge any fee on its investment in that scheme.

- (18) The asset management company shall not carry out its operations including trading desk, unit holder servicing and investment operations outside the territory of India:

Provided that the asset management company having any of its operations outside India shall wind up and bring them within the territory of India within a period of one year from the date of notification of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2011:

Provided further that the Board may grant a further period of one year if it is satisfied that there was sufficient cause for not winding up of the operation outside India within that period."

- (iii) in regulation 36, after sub-regulation (3), the following new sub-regulation shall be inserted, namely: -

"(4) The asset management company shall ensure that consolidated account statement for each calendar month is issued, on or before tenth day of succeeding month, detailing all the transactions and holding at the end of the month including transaction charges paid to the distributor, across all schemes of all mutual funds, to all the investors in whose folios transaction has taken place during that month:

Provided that the asset management company shall ensure that a consolidated account statement every half yearly (September/ March) is issued, on or before tenth day of succeeding month, detailing holding at the end of the six month, across all schemes of all mutual funds, to all such investors in whose folios no transaction has taken place during that period:

Provided further that the asset management company shall identify common investor across fund houses by their permanent account number for the purposes of sending consolidated account statement.

Explanation:- For the purpose of this regulation, the word 'transaction' shall include purchase, redemption, switch, dividend payout, dividend reinvestment, systematic investment plan, systematic withdrawal plan, systematic transfer plan and bonus transactions.

- (iv) in regulation 43, in sub-regulation (1) --
(a) in clause (f), for the full stop, the figure and word " ; or" shall be substituted;
(b) after clause (f), the following new clause shall be inserted, namely:-
"(g) infrastructure debt instrument and assets as specified in clause (1) of regulation 49L."
- (v) in regulation 44, sub-regulation (3) shall be substituted with the following, namely:-
"(3) Save as otherwise expressly provided under these regulations, the mutual fund shall not advance any loans for any purpose."
- (vi) after chapter VIA, the following chapter and regulations shall be inserted, namely: -

"CHAPTER VI-B INFRASTRUCTURE DEBT FUND SCHEMES

Definitions

49L. For the purposes of this Chapter, unless the context otherwise requires-

- (1) "Infrastructure debt fund scheme" means a mutual fund scheme that invests primarily (minimum 90% of scheme assets) in the debt securities or securitized debt instrument of infrastructure companies or infrastructure capital companies or infrastructure projects or special purpose vehicles which are created for the purpose of facilitating or promoting investment in infrastructure, and other permissible assets in accordance with these regulations or bank loans in respect of completed and revenue generating projects of infrastructure companies or projects or special purpose vehicles.
- (2) "Infrastructure" includes the sectors as specified by guidelines issued by the Board or as notified by Ministry of Finance, from time to time.
- (3) 'Strategic Investor' means;
 - (i) an Infrastructure Finance Company registered with Reserve bank of India as Non Banking Financial Company;
 - (ii) a Scheduled Commercial Bank;
 - (iii) International Multilateral Financial Institution.

49M. Applicability

- (1) The provisions of this chapter shall apply to infrastructure debt fund schemes launched by mutual funds.
- (2) All other provisions of these regulations and the guidelines and circulars issued thereunder, unless the context otherwise require or repugnant to the provisions of this chapter, shall apply to infrastructure debt fund schemes, trustees and asset management companies in relation to such schemes.

49N. Eligibility criteria for launching infrastructure debt fund scheme

- (1) An existing mutual fund may launch an infrastructure debt fund schemes if it has an adequate number of key personnel having adequate experience in infrastructure sector.
- (2) A certificate of registration may be granted under regulation 9 to an applicant proposing to launch only infrastructure debt fund schemes if the sponsor or the parent company of the sponsor: -
 - (a) has been carrying on activities or business in infrastructure financing sector for a period of not less than five years;
 - (b) fulfills eligibility criteria provided in Regulation 7.

Explanation- For the purpose of this clause, 'parent company of the sponsor' shall mean a company which holds at least 75% of paid up equity share capital of the sponsor.

49O. Conditions for infrastructure debt fund schemes

- (1) An infrastructure debt fund scheme shall be launched either as close-ended scheme maturing after more than five years or interval scheme with lock-in of five years and interval period not longer than one month as may be specified in the scheme information document.
- (2) Units of infrastructure debt fund schemes shall be listed on a recognized stock exchange, provided that such units shall be listed only after being fully paid up.

3323 GZ/11-5

- (3) Mutual Funds may disclose indicative portfolio of infrastructure debt fund scheme to its potential investors disclosing the type of assets the mutual fund will be investing.
- (4) An infrastructure debt fund scheme shall have minimum five investors and no single investor shall hold more than fifty percent of net assets of the scheme.
- (5) No infrastructure debt fund scheme shall accept any investment from any investor which is less than Rupees one crore.
- (6) The minimum size of the unit shall be Rupees ten lakhs.
- (7) Each scheme launched as infrastructure debt fund scheme shall have firm commitment from the strategic investors for contribution of an amount of at least Rupees twenty five crores before the allotment of units of the scheme are marketed to other potential investors.
- (8) Mutual Funds launching infrastructure debt fund scheme may issue partly paid units to the investors, subject to following conditions:
 - (a) The asset management company shall call for the unpaid portions depending upon the deployment opportunities;
 - (b) The offer document of the scheme shall disclose the interest or penalty which may be deducted in case of non payment of call money by the investors within stipulated time; and
 - (c) The amount of interest or penalty shall be retained in the scheme.

49P. Permissible investments

- (1) Every infrastructure debt fund scheme shall invest at least ninety percent of the net assets of the scheme in the debt securities or securitized debt instruments of infrastructure companies or projects or special purpose vehicles which are created for the purpose of facilitating or promoting investment in infrastructure or bank loans in respect of completed and revenue generating projects of infrastructure companies or special purpose vehicle.
- (2) Subject to sub-regulation (1), every infrastructure debt fund scheme may invest the balance amount in equity shares, convertibles including mezzanine financing instruments of companies engaged in infrastructure, infrastructure development projects, whether listed on a recognized stock exchange in India or not; or money market instruments and bank deposits.
- (3) The investment restrictions shall be applicable on the life-cycle of the infrastructure debt fund scheme and shall be reckoned with reference to the total amount raised by the infrastructure debt fund scheme.
- (4) No mutual fund shall, under all its infrastructure debt fund schemes, invest more than thirty per cent of its net assets in the debt securities or assets of any single infrastructure company or project or special purpose vehicles which are created for the purpose of facilitating or promoting investment in infrastructure or bank loans in respect of completed and revenue generating projects of any single infrastructure company or project or special purpose vehicle.
- (5) An infrastructure debt scheme shall not invest more than 30% of the net assets of the scheme in debt instruments or assets of any single infrastructure company or project or special purpose vehicles which are created for the purpose of facilitating or promoting investment in infrastructure or bank loans in respect of completed and revenue generating projects of any single infrastructure company or project or special purpose vehicle, which are rated below investment grade or unrated:

Provided that such investment limit may be extended upto 50% of the net assets of the scheme with the prior approval of the board of trustees and the board of asset management company.

(6) No infrastructure debt fund scheme shall invest in --

- (i) Any unlisted security of the sponsor or its associate or group company;
- (ii) Any listed security issued by way of preferential allotment by the sponsor or its associate or group company;
- (iii) Any listed security of the sponsor or its associate or group company or bank loan in respect of completed and revenue generating projects of infrastructure companies or special purpose vehicles of the sponsor or its associate or group companies, in excess of twenty five per cent of the net assets of the scheme, subject to approval of trustees and full disclosures to investors for investments made within the aforesaid limits; or
- (iv) Any asset or securities owned by the sponsor or asset management company or its associates, in excess of 20% of the net assets of the scheme not below investment grade, subject to approval of trustees and full disclosures to investors for investments made within the aforesaid limits.

49Q. Valuation of assets and declaration of net asset value

- (1) The assets held by an infrastructure debt fund scheme shall be valued "in good faith" by the asset management company on the basis of appropriate valuation methods based on principles approved by the trustees.
- (2) The valuation shall be documented and the supporting data in respect of each security so valued shall be preserved at least for a period of five years after the expiry of the scheme.
- (3) The methods used to arrive at values 'in good faith' shall be periodically reviewed by the Trustees and by the statutory auditor of the mutual fund.
- (4) The valuation policy approved by the board of asset management company shall be disclosed in the scheme information document.
- (5) The net asset value of every infrastructure debt fund scheme shall be calculated and declared atleast once in each quarter.

49R. Duties of asset management company

- (1) The asset management company shall lay down an adequate system of internal controls and risk management.
- (2) The asset management company shall exercise due diligence in maintenance of the assets of an infrastructure debt fund scheme and shall ensure that there is no avoidable deterioration in their value.
- (3) The asset management company shall record in writing, the details of its decision making process in buying or selling infrastructure companies' assets together with the justifications for such decisions and forward the same periodically to trustees.
- (4) The asset management company shall ensure that investment of funds of the Infrastructure Debt Fund schemes is not made contrary to provisions of this chapter and the trust deed.
- (5) The asset management company shall obtain, wherever required under these regulations, prior in-principle approval from the recognized stock exchange(s) where units are proposed to be listed.

- (6) The asset management company shall institute such mechanisms as to ensure that proper care is taken for collection, monitoring and supervision of the debt assets by appointing a service provider having extensive experience thereof, if required.

49S. Disclosures in offer document and other disclosures

- (1) The offer documents of infrastructure debt fund schemes shall contain disclosures which are adequate for investors to make informed investment decisions and such further disclosures as may be specified by the Board.
- (2) The portfolio disclosures and financial results in respect of an infrastructure debt fund schemes shall contain such further disclosures as may be specified by the Board.
- (3) Advertisements in respect of infrastructure debt fund schemes shall conform to such guidelines as may be specified by the Board.

49T. Transactions by employees etc.

- (1) All transactions done by the trustees or the employees or directors of the asset management company or the trustee company in the investee companies shall be disclosed by them to the compliance officer within one month of the transaction.
- (2) The compliance officer shall make a report thereon from the view point of possible conflict of interest and shall submit it to the trustees with his recommendations, if any.
- (3) The persons covered in sub-regulation (1) may obtain the views of the trustees before entering into the transaction in investee companies, by making a suitable request to them."

(vii) in regulation 56, -

a. in sub-regulation (1), the sign of full stop "." shall be substituted with the sign of colon ":";

b. after sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that the scheme wise annual report or abridged summary thereof may be sent to investors in electronic form on their registered e-mail address in the manner specified by the Board.";

c. after sub-regulation (3), the following new sub-regulation shall be inserted, namely: -

"(4) The asset management company shall display the link of the full scheme wise annual reports prominently on their website."

U.K. SINHA, Chairman

[ADVT III/4/69-ZB/11/Exty.]

Footnotes:-

1. The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, the Principal Regulations, were published in the Gazette of India on December 9, 1996 vide S.O.No. 856(F).

2. The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 were subsequently amended

(a) on April 15, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No.327(E).

(b) on January 12, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No.32(E).

(c) on December 08, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No.1223(E).

(d) on March 14, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.235(E).

(e) on March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.278(E).

(f) on May 22, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.484(E).

(g) on January 23, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.69(E).

(h) on May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.476(E).

(i) on July 23, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.698(E).

(j) on February 20, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.219(E).

(k) on June 11, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.625(E).

(l) on July 30, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.809(E).

(m) on September 9, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Fourth Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.956(E).

(n) on September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No.1045(E).

(o) on May 29, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O.No. 632(E).

(p) on January 12, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2004 vide F.No. SEBI/LAD/DOP/4/2004.

(q) on March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E).

(r) on January 12, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Amendment) Regulations, 2006 vide S.O.No. 38(E).

(s) on May 22, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2006 vide S.O.No. 783(E).

(t) on August 3, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2006 vide S.O.No. 1254(E).

(u) on December 27, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2006 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/82534/2006.

- (v) on December 27, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2006 vide F.No. SEBI/LAD/DOP/83065/2006.
- (w) on May 28, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2007 vide F. No. 11/LC/GN/2007/2518.
- (x) on October 31, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2007 vide F. No. 11/LC/GN/2007/4646.
- (y) on March 31, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. 11/LC/GN/2008/21669.
- (z) on April 16, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. LADNRO/ GN/2008/03/123042.
- (za) on May 22, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2008 vide No. LADNRO/GN/2008/09/126202.
- (zb) on September 29, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2008 vide No. LADNRO/ GN/2008/24/139426.
- (zc) on April 8, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009-10/01/159601.
- (zd) on June 5, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD- NRO/GN/2009-10/07/165404.
- (ze) on July 29, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2010 vide No. No. LAD-NRO/GN/2010-11/13/13945.
